

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 8/2022

बिमला पत्नी मुखराम उम्र 48 वर्ष, जाति माली, निवासी झड़ायानगर, तन पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

-अपीलांत

-बनाम-

राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।

-रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी  
उनवानी सरकार बनाम रामनिवास वगैरह मु0न0 03/2021  
अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 निर्णय दिनांक 17.09.2021

उपस्थिति:-

1. श्री मनोहरलाल, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोंडेंट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.09.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामनिवास, मु0 नं0 03/2021 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि - अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना एवं बिना न्यायिक विवेचना किये तथा अपना माईन्ड अप्लाई किये बिना ही निर्णय दिनांक 17.9.2021 पारित किया है, जो विरुद्ध कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकार्ड के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तरीफ में नहीं आता है। अपीलांत ने दिनांक 22.2.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपना जवाब नोटिस पेश कर दिया था । उसके बाद से लगातार अपीलांत की अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुंझुनू

की आर्डरशीट दिनांक 3.3.2021 से अनुपस्थिति दिखाई है। अपीलांट स्वयं तारीख पेशियों पर हाजिर होती रही है, लेकिन उसके बाद में दिनांक 12.4.2021 को अपीलांट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.4.2021 बताई गई, उसके बाद कोविड-19 के चलते सम्पूर्ण न्यायालय में लॉकडाउन होने के कारण कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और अपीलांट की लगातार अनुपस्थिति दिखते हुये अपीलांट को बिना सुने ही दिनांक 17.9.2021 को बिना माईन्ड अप्लाई किये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। ग्राम झड़ायानगर के हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 1.58 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह पर करीब 100 लोग मकान व बाड़े बनाकर रिहायश कर रहे है जो आबादी भूमि है जिस पर अपीलांट करीब 50 साल से बाड़ा बनाकर आबाद हैं तथा समान के अन्य 40 परिवार करीब 50 वर्षों से पुक्ता मकान व बाड़े बनाकर आबाद है। उक्त भूमि रिहायश करने के लिए गांव के व्यक्तियों के ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी थी। अपीलांट का पुराना कब्जा व ढाणी के लोगों की बसासत होने के कारण नियमन का मामला बनता है। उक्त भूमि पर अपीलांट के अलावा करीब 40 परिवार अपने मकान बनाकर आबाद हैं। अपीलांट के अलावा अन्य 40 घरों की आबादी को अतिक्रमी न मानकर केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से प्रेरित होकर एक मात्र प्रार्थी/अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर पेश करवाई है। एक तरफ तो राज्य सरकार भूमिहीन लोगों को भूखण्ड आवंटित कर उन्हें इन्द्रा आवास व अन्य योजनाओं के तहत मकान बनाकर आबाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब तबके के बसे हुये लोगों को अतिक्रमी घोषित कर उनके खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया जा रहा है।

अपीलांट का कथन है कि वर्तमान समय में ग्राम झड़ायानगर पटवार हल्का पचलंगी का सरपंच व उसका परिवार अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता रखता है, इसलिये हल्का पटवारी से मिलकर केवल अकेले प्रार्थी को ही नोटिस दिया गया है, जबकि हाल सरपंच व उसके परिवार के अन्य कई लोगों ने उक्त हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 01.58 हैक्टर की भूमि पर बाड़ा व आवास बना रखे व कृषि के काम ले रहे हैं। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 17.9.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर विवादित भूमि का अपीलांट के नियमन करने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया।

21/9/21  
अतिरिक्त जिला बरकर  
इन्द्रा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि— अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना एवं बिना न्यायिक विवेचना किये तथा अपना माईन्ड अप्लाई किये बिना ही निर्णय दिनांक 17.9.2021 पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तरीफ में नहीं आता है। ग्राम झड़ायानगर के हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 1.58 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह पर करीब 100 लोग मकान व बाड़े बनाकर रिहायश कर रहे हैं, जो आबादी भूमि है जिस पर अपीलांट करीब 50 साल से बाड़ा बनाकर आबाद हैं तथा समान के अन्य 40 परिवार करीब 50 वर्षों से पुक्ता मकान व बाड़े बनाकर आबाद है। उक्त भूमि रिहायश करने के लिए गांव के व्यक्तियों के ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी थी। अपीलांट का पुराना कब्जा व ढाणी के लोगों की बसासत होने के कारण नियमन का मामला बनता है। उक्त भूमि पर अपीलांट के अलावा करीब 40 परिवार अपने मकान बनाकर आबाद हैं। अपीलांट के अलावा अन्य 40 घरों की आबादी को अतिक्रमी न मानकर केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से प्रेरित होकर एक मात्र प्रार्थी/अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर पेश करवाई है। वर्तमान समय में ग्राम झड़ायानगर पटवार हल्का पचलंगी का सरपंच व उसका परिवार अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता रखता है, इसलिये हल्का पटवारी से मिलकर केवल अकेले प्रार्थी को ही नोटिस दिया गया है, जबकि हाल सरपंच व उसके परिवार के अन्य कई लोगों ने उक्त हाल खसरा नंबर 2261 कुल रकबा 1.58 हैक्टर की भूमि पर बाड़ा व आवास बना रखे व कृषि के काम ले रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 17.9.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर विवादित भूमि का अपीलांट के नियमन करने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय

2021/1  
अतिरिक्त जिला जज  
इन्दौर

पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांत बी0पी0एल0 परिवार से है। विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से पिछले 50 साल से काबिज है। मौके पर लगभग 40 परिवार आबाद है। विधुत संबंध है। राजनैतिक कारणों से केवल अपीलांत के विरुद्ध बेदखली का आदश पारित किया गया है। अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांत स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.9.2021 उनवानी सरकार बनाम रामनिवास वगैरह मु0नं0 03/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

( जगदीश प्रसाद गोड़ )  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जगदीश प्रसाद गोड़ )  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू